>

Title: Issue rgarding National Housing Policy in the country.

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): सभापति जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक नीतिगत मामला है। सरकार प्रत्येक वर्ष 5 से 6 हजार करोड़ रुपये इंदिरा आवास योजना के तहत देती है। इंदिरा आवास बनाने का जो मानक है, वह 108 स्क्वायर फिट का घर होता है। सरकार आम आदमी के नाम पर चल रही है। आम आदमी के जीवन को हमने इतना सब-स्टैंडर्ड कर दिया है और इस संबंध में मेरा सरकार से आग्रह है कि पहले एक समय था कि सरकार इसके लिए 10000 रुपये देती थी, फिर 20,000 रुपये किया और 40,000 दिया और अब 70,000 रुपये देती है। लेकिन इससे बात नहीं बनती है। कम से कम आवास की सुविधा अगर आप आम आदमी को राष्ट्रीय आवास नीति बनाकर देना चाहते हैं तो कम से कम ग्रामीण स्तर पर दो कमरे का आवास बनाकर देना चाहिए जिसमें बरामदा हो, किचन हो, टॉयलेट हो, तब तो एक आदमी को बेहतर जीवन देने की बात आप कर रहे हैं वर्ना सिर्फ पैसा बांटने से काम नहीं बनता है। सरकार अभी जिस तरीके से फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आई है, मैं सरकार पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। कल इन नीतियों की खामियों पर कोई बात न उठे, इसलिए लिहाजा उन नीतियों को हम बेहतर तरीके से यदि देश में लागू करेंगे तो अच्छा होगा। मैं अभी एक छोटे से देश श्रीलंका में गया था, ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपने राष्ट्रीय आवास नीति की बात कही। वह अच्छी थी।

â€¦(व्यवधान)

श्री धनंजय सिंह : सभापति जी, इसी में मुझे केवल एक बात कहनी थी कि हमसे श्रीलंका बहुत गरीब देश है, वहां की सरकार ने जो क्राइटीरिया रखा है, अभी हमारे एक साथी श्रीलंका का विषय उठा रहे थे, उसमें नॉर्थ प्रोविंस में जब रीहैबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा था, वहां भारत सरकार ही दो दो कमरों का मकान बनाकर दे रही है। इंडियन करेंसी में 3 लाख 60,000 रुपये हम दे रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम वैसी व्यवस्था हमें अपने देश में भी आम आदमी के लिए लागू करनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अशोक अर्गल और श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय जी को श्री धनंजय सिंह द्वारा उठाये गये विषय के साथ एसोशिएट किया जाता है।